पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2024 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या - 14957

==========

मेसर्स ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय तीसरी मंजिल, आस्था भवन, मिस मंडल परिसर, डाकघर- एस. के. पुरी, थाना- बुद्ध कॉलोनी, बोरिंग रोड चौराहा, पटना, बिहार, 800001 अपने निदेशक मुस्तफा हुसैन, पुरुसः-, आयु-48 वर्ष पुत्र्र- सैयद मंजर हुसैन निवासी-102, शक्ति सदन अपार्टमेंट, आशियाना दीघा रोड, डाकघर -बी. वी. कॉलेज, थाना-शास्त्री नगर, राजा बाजार, रुकनपुरा, जिला-पटना, बिहार-800014 के माधयम से।

.... याचिकाकर्त्ता

बनाम

1. बिहार राज्य,प्रधान सचिव सह आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार के माध्यम से।
2. सहायक राज्य कर आयुक्त, पटना विशेष सर्कल, पटना, बिहार।
3. राज्य कर (अपील) के अतिरिक्त आयुक्त, केंद्रीय प्रभाग, पटना, बिहार।

....प्रत्यर्थीगण

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री अनुभव खोवाला,
प्रत्यर्थीओं के अधिवक्ता : श्री विवेक प्रसाद, जीपी-7

==========

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम (सीजीएसटी), 2017--- बिहार माल और सेवा कर अधिनियम (बीजीएसटी), 2017---धारा 107, 73(9), 50--- सीमा अधिनियम, 1963---धारा 4, 12(1),(2)--- सामान्य खंड अधिनियम---धारा 9--- सीजीएसटी/बीजीएसटी अधिनियम के तहत अपील दायर करने के लिए निर्धारित अवधि की गणना--- अपीलीय आदेश को रद्द करने के लिए रिट याचिका जिसके तहत और याचिकाकर्ता की अपील को विवादित मांग आदेश के खिलाफ केवल सीमा के आधार पर खारिज कर दिया गया था---यह दलील कि अपीलीय प्राधिकारी ने गलत दृष्टिकोण अपनाया है कि अपील दायर करने

के लिए आदेश के संचार की तारीख से चार महीने (एक महीने की क्षमा अवधि सहित) की समय सीमा 120 दिनों के बराबर है न कि चार कैलेंडर महीनों के बराबर--- निष्कर्ष: जिस तारीख को याचिकाकर्ता को अपीलीय आदेश प्राप्त हुआ था, उसे निर्धारित सीमा अवधि की गणना में शामिल नहीं किया जा सकता है --- अपील तीन महीने की निर्धारित सीमा अवधि की समाप्ति के बाद एक महीने के भीतर पेश की गई थी --- न्याय निर्णयन प्राधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि 27.03.2024 को समाप्त हो गई थी --- अपीलकर्ता एक महीने की अतिरिक्त अवधि यानी 27.04.2024 के भीतर अपील कर सकता था, जिसमें अपीलीय प्राधिकारी को यह संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाए गए थे कि अपीलकर्ता को एक महीने की अतिरिक्त अवधि के भीतर अपील पेश करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था --- अपील 26.04.2024 को पेश की गई थी, इसलिए अपीलीय प्राधिकारी को देरी को माफ करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा दिखाए गए कारण पर विचार करना आवश्यक था --- अपीलीय प्राधिकारी ने सीजीएसटी/बीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 के तहत विधायी योजना की सराहना करने में पूरी तरह से गलती की है --- अपील दायर करने की अवधि तीन महीने होगी और इसे एक महीने की अतिरिक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है, बशर्ते कि निर्धारित समय सीमा के भीतर अपील न करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी को पर्याप्त कारण दिखाया जाए --- विवादित आदेश को रद्द किया जाता है --- रिट को अनुमति दी जाती है।

(पैरा- 21, 28, 30, 31)

(2014) 11 एससीसी 769, (1999) 3 एससीसी 1, (1999) 4 एससीसी 567, (1972) 1 एससीसी 639, (2000) 8 एससीसी 649, (2001) 7

*एससीसी 197, (2010) 12 एससीसी 210, (2012) 2 एससीसी 624, (2003) 5 एससीसी 448 ..... **संदर्भित***

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

==========

कोरम - माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद
और
माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

मौखिक आदेश

(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद)

तारीखः04-02-2025

निम्नलिखित राहतों के लिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है:-

"(i) अपीलीय आदेश एपीएल - 02 प्रपत्र में, संदर्भ संख्या, ZD1100524014826Q दिनांक 18.05.2024 के साथ में , ZD1100524014826Q दिनांक 18.05.2024 के साथ-साथ प्रत्यर्थीसंख्या-3 द्वारा जारी एक विस्तृत आदेश ज्ञापन संख्या 529 दिनांक 18.05.2024 को रद्द करने के लिए उत्पप्रेसण या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-107 के तहत की गई अपील (इसके बाद संक्षेप में "सी. जी. एस. टी., अधिनियम 2017" के रूप में संदर्भित) या बिहार वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (इसके बाद संक्षेप में बी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 के रूप में संदर्भित), बी. जी. एस. टी./सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 73 (9) के तहत प्रत्यर्थी जी. एस. टी एपीएल-01 प्रपत्र में प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित विवादित मांग आदेश के खिलाफ, डी. आर. सी.-7 प्रपत्र में अपने संक्षिप्त आदेश के साथ में अपने संक्षिप्त आदेश के साथ संदर्भ संख्या ZD1012230343049 में

अधिनियम की धारा-50 के तहत 77,97004 रुपये का ब्याज 21,21,878 रुपये कर की मांग कर रहा है, तथा जुलाई 2017-मार्च 2018 (अनुलग्नक पी/2) की कर अवधि के लिए जुर्माना 8,12,188/-, रुपये को सीमा के एकमात्र आधार पर खारिज कर दिया गया है।

(ii) **प्रत्यर्थी** संख्या 3 पर एक याचिका या आदेश या निर्देश जारी करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा 26.04.2024 (अनुलग्नक पी/3 सीरीज) पर प्रपत्र जीएसटी एपीएल-01 में दायर अपील को ग्रहण और स्वीकार करने के लिए, जिसमे **प्रत्यर्थी** संख्या 2 द्वारा पारित विवादित मांग आदेश के खिलाफ, **प्रत्यर्थी** संख्या 3 के रूप में बिना विवेक के उचित अनुप्रयोग के, सी. जी. एस. टी./बी. जी. एस. टी. अधिनियम 2017 की धारा 107 के प्रावधानों की गलत व्याख्या करते हुए यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि संचार की तारीख से चार महीने (एक महीने की माफ करने योग्य अवधि सहित) की समय सीमा भीतर अपील दायर नहीं की गई है, भले ही 120 दिनों के बराबर है, न कि चार कैलेंडर महीनों के लिए, यह सी. जी. एस. टी./बी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 107 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर दायर किया गया था, लेकिन योग्यता के आधार पर अपील की सुनवाई किए बिना, अपील दायर करने का आदेश इस अपील को स्वीकार करने के चरण में विवादित अपील आदेश दिनांक 18.05.2023 को पारित करके खारिज कर दिया गया है और **प्रत्यर्थी** संख्या 3 की ये कार्रवाइयां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और सी. जी. एस. टी./बी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 107 के प्रावधानों का उल्लंघन हैं और **प्रत्यर्थी** संख्या 3 को याचिकाकर्ता को अपील की स्वीकृति के बारे में सूचित करने और सी. जी. एस. टी./बी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की योजना के अनुसार याचिकाकर्ता को अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद ए. पी. एल.-04 में अपील आदेश जारी करके योग्यता के आधार पर अपील पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जा सकता है।

(iii) इस याचिका आवेदन के लंबित रहने के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित किए गए विवादित आदेश के संदर्भ में मांगी गई कर, ब्याज और जुर्माने की शेष राशि की वसूली के लिए कोई दंडात्मक कार्रवाई करने से प्रत्यर्थी और उक्त प्रत्यर्थी द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश को निष्पादित करने वाले किसी भी अन्य प्राधिकरण को रोकने के लिए एक रिट या आदेश या निर्देश जारी करने के लिए।

(iv) किसी अन्य उपयुक्त याचिका , आदेश या निर्देश को आगे जारी करने के लिए, जिसे यह माननीय न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे।"

मामले के संक्षिप्त तथ्य

2. याचिकाकर्ता कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय पटना में है।यह बिहार राज्य में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (इसके बाद 'सी. जी. एस. टी. अधिनियम' या '2017 का अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के तहत जी. एस. टी. आई. एन. संख्या 10ए. ए. ए. ए. सी. टी. 5131ए. आई. जेड. सी. द्वारा पंजीकृत है। यह कहा गया है कि प्रासंगिक नियमों के साथ पठित सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धाराओं के प्रावधान बिहार वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसके बाद 'बी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017' कहा जाता है) के प्रावधानों के समान हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से दलील

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या-2 द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ एक जी. एस. टी. कार्यवाही बीजीएसटी/सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 73 (1) के तहत 2

जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक की कर अवधि के लिए कारण दर्शाओ नोटिस जारी करके शुरू की गई थी। कारण दर्शाओ नोटिस में, याचिकाकर्ता को धारा 50 के तहत ब्याज के साथ 81,21,878 रुपये तथा साथ रु 77,97,004 और 8,12,187 रुपये क्रमशःका जुर्माना की कर की बकाया मांग का भुगतान करने का निर्देश जारी किया गया था। याचिकाकर्ता से 27.09.2023 पर या उससे पहले अपना जवाब जमा करने के लिए कहा गया था। 10.10.2023 पर व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख तय की गई थी।कारण दर्शाओ नोटिस की एक प्रति याचिका आवेदन के अनुलग्नक 'पी/1' के रूप में संलग्न की गई है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अनुलग्नक 'पी/1' के अवलोकन पर सुनवाई की तारीख तय की गई है, लेकिन इसे एक प्रभावी तारीख के रूप में नहीं लिया जाएगा।

4. यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या - 2 ने याचिकाकर्ता को 08.12.2023 द्वारा अपना जवाब जमा करने के लिए दो अनुस्मारक नोटिस जारी किए।उन नोटिसों के जवाब में, याचिकाकर्ता ने अपने एक आपूर्तिकर्ता की अनुपलब्धता के कारण खरीद विवरणों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए पंद्रह दिनों के अतिरिक्त समय का अनुरोध करते हुए अपना जवाब दाखिल किया।इसके बाद, प्रत्यर्थी संख्या 3 ने दिनांक 22.10.2023 का एक अनुस्मारक नोटिस जारी किया जिसमें याचिकाकर्ता को 2024 का अपना जवाब अगले दिन तक देने के लिये कहा गया था। उन पत्राचारों को अभिलेख पर नहीं लाया गया है क्योंकि याचिकाकर्ता के अनुसार, वर्तमान याचिका आवेदन में शामिल मुद्दे के प्रकार में, वे बहुत प्रासंगिक नहीं हैं।

5. याचिकाकर्ता सी. जी. एस. टी.-बी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 73 (9) के तहत अंतिम मांग आदेश दिनाक 27.12.2023 से दुखी और असंतुष्ट है, जिसमें प्र्रपत्र डी. आर. सी.-07 में इसके संक्षिप्त आदेश के साथ 81,21,878-और ब्याज आदि के कर की मांग की गई है। दिनांक 27.12.2023 की मांग आदेश सूचना की एक प्रति और प्रपत्र जी. एस. टी. डी. आर. सी.-07 में आदेश का सारांश याचिका आवेदन के लिए अनुलग्नक 'पी/2' है।

6. याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी सं.-3 के समक्ष दिनांक-26.04.2024 कोप्रपत्र जी. एस. टी. ए. पी. एल.-1 में सी. जी. एस. टी./बी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 107 के तहत अपील के अपने उपाय का लाभ उठाते हुए ऑनलाइन अपील को प्राथमिकता दी।यह उनका निवेदन है कि याचिकाकर्ता कंपनी के निदेशक के खराब स्वास्थ्य के कारण 2017 के अधिनियम की धारा 107 (1) के तहत आदेश के संचार की तारीख से तीन महीने की वैधानिक समय सीमा के भीतर अपील दायर नहीं की जा सकी। हालाँकि, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपील 2017 के अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (4) के तहत प्रदान की गई एक महीने की क्षम्य अवधि के भीतर दायर की गई थी।अपीलार्थी ने अपील देरी से दायर करने के कारणों के बारे में बताया। ।इस संबंध में, विद्वान वकील ने दिखाया है कि प्र्रपत्र जी. एस. टी. ए. पी. एल.-01 में कारणों का उल्लेख किया गया है। अपीलार्थी ने 2017 के अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (6) के संदर्भ में विवादित कर राशि के दस प्रतिशत की पूर्व-जमा राशि का भी भुगतान किया।

7. हालाँकि, अपीलीय प्राधिकरण ने प्रवेश स्तर पर ही ए. पी. एल.-02 संदर्भ संख्या- ZD100524014826Q, दिनांक 18.05.2024- के साथ-साथ एक आदेश धारक ज्ञापन संख्या 529 दिनांक 18.05.2024 के साथ, केवल अपील दायर करने में देरी के आधार पर जारी करके अपील को खारिज कर दिया। अपीलीय आदेश की एक प्रति रिकॉर्ड अनुलग्नक 'पी/4' श्रृंखला में रखी गई है।याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलीय प्राधिकरण ने एक गलत दृष्टिकोण अपनाया है कि आदेश के संचार की तारीख से 120 दिनों की समय अवधि (एक महीने की विस्तारित अवधि सहित) के भीतर अपील दायर करने की आवश्यकता थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान अपीलीय प्राधिकारी द्वारा व्यक्त किए गए विचार क़ानून के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले **हिमाचल प्रदेश राज्य तथा अन्य** बनाम **हिमाचल टेक्नो इंजीनियर्स और अन्य (2010) 12 एस. सी. सी. 210, बीबी सलमा खातुन बनाम बिहार राज्य,-एस सी सी (2001)7-197 तथा एकोन ईंडस्ट्रिरज लिमिटेड बनाम रोम ईंडस्ट्रिरज लिमिटेड, एस.सी.सी-(2014)-11-769** में भी हैं।

8. विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाल के एक फैसले पर भरोसा किया है **पश्चिम बंगाल राज्य, प्रतिनिधित्व सचिव और अन्य बनाम राजपथ कॉन्ट्रैक्टर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड 7 एस सी आर 1; 2024 आईएनएससी 477** में सूचित है जिसमे यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता की अपील को अस्वीकार करने वाला विवादित अपीलीय आदेश कानूनी रूप से गलत है और इसे दरकिनार किया जा सकता है।

राज्य का कथन

9. श्री विवेक प्रसाद, विद्वान जी. पी.-7 ने जवाबी हलफनामे में किए गए कथनों के आधार पर याचिका आवेदन का विरोध किया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलीय प्राधिकरण ने अपील को सही ढंग से खारिज कर दिया है क्योंकि यह न तो मूल्यांकन आदेश के तीन महीने के भीतर और न ही आगे एक महीने की विस्तारित अवधि के भीतर दायर किया गया था।

10. विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि एक महीने को तीस दिन की अवधि माना जाता है। इस संबंध में, **मैसर्स वैष्णवी एंटरप्राइजेज बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय** का निर्णय निर्दिष्ट किया गया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे मामले में जहां निर्णय आदेश करदाता को 14.05.2023 पर सूचित किया गया था, अपील 12.08.2023 पर या उससे पहले दायर की जानी थी, इसके अलावा, यदि धारा 107 (4) के तहत एक महीने की और अवधि प्रदान की गई है, नवीनतम अपील 11.09.2023 द्वारा तक दायर की जानी चाहिए थी। यह उनका निवेदन है कि कई मामलों में, माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भी इसी तरह का विचार रखा है।इस प्रकार, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता का दावा कि चार महीने की अवधि 26.04.2024 पर समाप्त नहीं हुई थी, जिस तारीख को तत्काल मामले में अपील दायर की गई थी, गलत और निराधार है।

11. विद्वान अधिवक्ताजी. पी.-7 के कथनो पका जवाब देते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि **मेसर्स वैष्णवी**

एंटरप्राइजेज (उपरोक्त) के वाद में दिये गये निर्णय में और ऊपर उल्लिखित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में भी 2017 के अधिनियम की धारा 107 की योजना को दरकिनार किया गया है। कालिका कौर उर्फ कालिका सिह तथा अन्य बनाम बिहार राज्य (2003) 5 एस. सी. सी. 448 (पैराग्राफ 5,6 तथा7) में रिपोर्ट की गईमामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए (**यह प्रस्तुत किया जाता है कि मैसर्स वैष्णवी एंटरप्राइजेज (उपरोक्त) का निर्णय अनवधानता के कारण होगा।**

<u>विचार करें</u>

12. अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचनों से पता चलता है कि वर्तमान याचिका आवेदन में शामिल एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या 2017 के अधिनियम की धारा 107 उप-धारा (1) और (4) में उल्लिखित तीन महीने की अवधि और (एक महीने की अवधि की व्याख्या क्रमशः नब्बे दिनों और तीस दिनों की अवधि के रूप में की जा सकती है जैसा कि विद्वान अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है?जबकि याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवकता का यह तर्क है कि विधानसभाओं ने अपने विवेक से अपील दायर करने के लिए तीन महीने की सीमा की अवधि प्रदान की है और एक महीने की क्षम्य अवधि प्रदान की है, कोई भी व्याख्या जो सीमा की अवधि को क्रमशः नब्बे दिन और तीस दिन के रूप में मानती है, गलत होगी।

13. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय प्राधिकरण के इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है कि एक महीने को केवल उस तारीख से तीस दिन के रूप में लिया जाए जिस दिन कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था।

14. इस स्तर पर, हम 2017 के अधिनियम की धारा 107 को एक तैयार संदर्भ के लिए उद्धृत करते हैंः

107 अपीलीय प्राधिकरण से अपील

"(1) इस अधिनियम या राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम या केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित किसी भी निर्णय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति उस तारीख से तीन महीने के भीतर ऐसे अपीलीय प्राधिकरण में अपील कर सकता है जिस दिन उक्त निर्णय या आदेश को ऐसे व्यक्ति को सूचित किया जाता है।

(2) आयुक्त, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, या राज्य कर आयुक्त या केंद्र शासित प्रदेश कर आयुक्त के अनुरोध पर, किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड की मांग और जांच कर सकता है जिसमें एक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने इस अधिनियम के तहत कोई निर्णय या आदेश पारित किया है।

1. प्रवर्तन w.e.f.-1-7-2017 वीडियो सूचना।नं. 9/2017-केंद्रीय कर, या राज्य वस्तु और सेवा कर अधिनियम या केंद्र शासित प्रदेश वस्तु और सेवा कर अधिनियम, उक्त निर्णय या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से और आदेश द्वारा, अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को निर्देश दे सकता है कि वह उक्त निर्णय या आदेश के संचार की तारीख से छह महीने के भीतर अपीलीय प्राधिकरण को उक्त निर्णय या आदेश से उत्पन्न होने वाले ऐसे बिंदुओं के निर्धारण के लिए आवेदन करे जो आयुक्त द्वारा अपने आदेश में निर्दिष्ट किए जाएं।

(3) जहां, उप-धारा (2) के तहत एक आदेश के अनुसरण में, अधिकृत अधिकारी अपीलीय प्राधिकरण को एक आवेदन करता है, ऐसे आवेदन पर अपीलीय प्राधिकरण द्वारा इस तरह से कार्रवाई की जाएगी जैसे कि यह निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के निर्णय या आदेश के खिलाफ की गई अपील थी और ऐसा अधिकृत अधिकारी एक अपीलार्थी था और अपील से संबंधित

इस अधिनियम के प्रावधान ऐसे आवेदन पर लागू होंगे।

(4) अपीलीय प्राधिकरण, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलार्थी को तीन महीने या छह महीने की उपरोक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो इसे एक महीने की आगे की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।

(5) इस धारा के तहत प्रत्येक अपील ऐसे रूप में होगी और ऐसी तरीके से सत्यापित की जाएगी जो निर्धारित की जाए।

(6) उप-धारा (1) के तहत कोई अपील दायर नहीं की जाएगी, जब तक कि अपीलार्थी ने -

(क) आक्षेपित आदेश से उत्पन्न कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क और जुर्माने की राशि का पूरा हिस्सा, जैसा कि उसके द्वारा स्वीकार किया जाता है; और

(b) दस प्रतिशत के बराबर राशि।उक्त आदेश से उत्पन्न विवाद में कर की शेष राशि, (2) [अधिकतम (3) [बीस] करोड़ रुपये के अधीन,] जिसके संबंध में अपील दायर की गई हैः

2. सी. जी. एस. टी. (ए. एम. डी. टी.) द्वारा डाला गया। अधिनियम, 2018 (2018 का 31), ता.30-8-2018, डब्ल्यू. ई. एफ. 1-2-2019 वीडियो सूचना।नं. 02/2019-केंद्रीय कर, ता.29-1-2019

3. वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2024 (2024 का 15) द्वारा 'पँचिश' के लिए प्रतिस्थापित किया गया।16-8-2024,डब्ल्यू. ई. एफ. 1-11-2024 वीडियो एस. ओ. 4253 (ई), डी. टी.27-9-2024

(4) [बशर्ते कि धारा 129 की उप-धारा (3) के तहत किसी आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की जाएगी, जब तक कि पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि न हो।जुर्माने का भुगतान अपीलार्थी द्वारा किया गया है।]

(7) जहां अपीलार्थी ने उप-धारा (6) के तहत राशि का भुगतान किया है, वहां शेष राशि के लिए वसूली की कार्यवाही पर रोक

लगा दी गई मानी जाएगी।

(8) अपीलीय प्राधिकरण अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देगा।

(9) अपीलीय प्राधिकरण, यदि किसी अपील की सुनवाई के किसी भी चरण में पर्याप्त कारण दिखाया जाता है, तो पक्षों या उनमें से किसी को समय दे सकता है और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए अपील की सुनवाई को स्थगित कर सकता हैः

बशर्ते कि अपील की सुनवाई के दौरान किसी पक्ष को ऐसा कोई स्थगन तीन बार से अधिक नहीं दिया जाएगा।

(10) अपीलीय प्राधिकरण, किसी अपील की सुनवाई के समय, किसी अपीलार्थी को अपील के आधार में निर्दिष्ट नहीं किए गए किसी भी आधार को जोड़ने की अनुमति दे सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि अपील के आधार से उस आधार को छोड़ना जानबूझकर या अनुचित नहीं था।

(11) अपीलीय प्राधिकरण, ऐसी आगे की जांच करने के बाद, जो आवश्यक हो, ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह उचित और उचित समझता है, जिसके खिलाफ अपील किए गए निर्णय या आदेश की पुष्टि, संशोधन या रद्द करता है, लेकिन मामले को उस न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को वापस नहीं भेजेगा जिसने उक्त निर्णय या आदेश पारित किया थाः

बशर्ते कि अधिक मूल्य के माल को जब्त करने या जब्त करने या धनवापसी या निवेश कर क्रेडिट की राशि को कम करने के बदले में किसी भी शुल्क या जुर्माने या जुर्माने को बढ़ाने का आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी को प्रस्तावित आदेश के खिलाफ कारण दिखाने का उचित अवसर नहीं दिया गया हैः

4. वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा सम्मिलित, डब्ल्यू. ई. एफ. 1-1-2022 अधिसूचना के माध्यम से।नं. 39/2021-केंद्रीय कर, ता.

आगे यह प्रावधान किया गया है कि जहां अपीलीय प्राधिकरण की राय है कि किसी भी कर का भुगतान नहीं किया गया है या

अल्प-भुगतान या गलती से धनवापसी नहीं की गई है, या जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से लाभ उठाया गया है या उपयोग किया गया है, वहां अपीलार्थी को ऐसे कर या इनपुट टैक्स क्रेडिट का भुगतान करने की आवश्यकता वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी को प्रस्तावित आदेश के खिलाफ कारण दिखाने के लिए नोटिस नहीं दिया जाता है और आदेश धारा 73 या धारा 741 [या धारा 74 ए] के तहत निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पारित नहीं किया जाता है।

(12) अपील का निपटारा करने वाला अपीलीय प्राधिकरण का आदेश लिखित रूप में होगा और निर्धारण के लिए बिंदु, उस पर निर्णय और ऐसे निर्णय के कारण बताएगा।

(13) अपीलीय प्राधिकरण, जहाँ ऐसा करना संभव है, प्रत्येक अपील को उस तारीख जिस दिन इसे दायर किया गया हैः से एक वर्ष की अवधि के भीतर सुनेगा और निर्णय लेगा :बशर्ते कि जहां किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा आदेश जारी करने पर रोक लगाई जाती है, वहां इस तरह की रोक की अवधि को एक वर्ष की अवधि की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

(14) अपील के निपटारे पर, अपीलीय प्राधिकरण अपने द्वारा पारित आदेश को अपीलार्थी, प्रतिवादी और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को सूचित करेगा।

(15) अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की एक प्रति क्षेत्राधिकार आयुक्त या इस संबंध में उनके द्वारा नामित प्राधिकरण और राज्य कर के क्षेत्राधिकार आयुक्त या केंद्र शासित प्रदेश कर आयुक्त या इस संबंध में उनके द्वारा नामित प्राधिकरण को भी भेजी जाएगी।

(16) इस धारा के तहत पारित प्रत्येक आदेश, धारा 108 या धारा 113 या धारा 117 या धारा 118 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए अंतिम और पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।”

3. वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2024 (2024 का 15) द्वारा सम्मिलित किया गया।16-8-2024,डब्ल्यू. ई. एफ. 1-11-2024

वीडियो एस. ओ. 4253 (ई), डी. टी.27-9-2024

15. 2017 के अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (1) को पुरा पढ़ने पर, यह प्रतीत होता है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने के लिए निर्धारित अवधि उस तारीख से तीन महीने है जिस दिन उक्त निर्णय या आदेश उक्त व्यक्ति को सूचित किया जाता है। यह भी स्पष्ट है कि उप-धारा (4) के तहत, अपीलीय प्राधिकरण को एक महीने की और देरी को माफ करने की शक्ति है यदि अपीलीय प्राधिकरण का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को तीन महीने की उपरोक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।

16. **इकॉन एंट्री लिमिटेड** (उपरोक्त) के वाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित शब्दों में दिए गए एक संदर्भ पर विचार कर रहा थाः

> हमारे विचार में, अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये निर्णय साकेत इंडिया लिमिटेड बनाम इंडिया सिक्यूरिटीज लिमिटेड (2) में पुनर्विचार की आवश्यकता है। इस मामले को एक बड़ी पीठ के समक्ष रखने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश प्राप्त किए जा सकते हैं।"

17. साकेत इंडिया लिमिटेड बनाम इंडिया सिक्योरिटिज लिमिटेड के वाद में **(1999) 3 एस. सी. सी. 1** में सूचित, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधि के एक प्रश्न पर निम्नानुसार विचार कियाः

> 2. ... क्या परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा

> 138 के तहत दायर की गई शिकायत समय के भीतर या उससे आगे है क्योंकि यह तर्क दिया जाता है कि यह उस तारीख से एक महीने के भीतर दायर नहीं की गई है जिस दिन पर परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के परंतुक के खंड (सी) के तहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था?"

2. (1999) 3 एससीसी 1: एक ही प्रश्न को निम्नलिखित शब्दों में फिर से तैयार किया गया थाः

> "5. ... क्या धारा 142 (ख) के तहत निर्धारित एक महीने की अवधि की गणना करने के लिए उस अवधि की गणना उस तारीख को छोड़कर की जानी चाहिए जिस दिन कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था?"

18. साकेत इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) और **एस. आई. एल. आयात, यू. एस. ए.बनाम सहायक रेशम निर्यातकों** का मामला **(1999) 4 एस. सी. सी. 567** में अधिसुचित, **में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में भिन्नता पाई गई** इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को विचार के लिए लिया।यह पाया गया कि **साकेत इंडिया लिमिटेड** (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 12 (1) और (2) और सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 9 पर भरोसा किया था। इसके अलावा, इस बिंदु पर कई निर्णयों पर भरोसा करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **साकेत इंडिया लिमिटेड** (ऊपर) में कहा कि उस दिन को बाहर करने का सिद्धांत, जिससे अवधि की गणना की जानी है, सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 12 (1) और (2) में शामिल किया गया है। यही सिद्धांत सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 9 में भी शामिल किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **हारू**

दास गुप्ता बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1972) 1 एस. सी. सी. 639 में सूचित के वाद में अपने फैसले के पैराग्राफ '5' के प्रासंगिक भाग को संदर्भित किया।

जो हम एक तैयार संदर्भ के लिए यहाँ उद्धृत करते हैंः

> "5. ... नियम अच्छी तरह से स्थापित है कि जहां एक निश्चित तिथि से एक विशेष समय दिया जाता है जिसके भीतर एक कार्य किया जाना है, उस तारीख के दिन को बाहर रखा जाना है।
>
> ऐसे दिन से उस दिन तक की अवधि को परिभाषित करने का प्रभाव जिसके भीतर कोई कार्य किया जाना है, पहले दिन को बाहर करना और अंतिम दिन को शामिल करना है।"

19. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **एकॉन एंट्री लिमिटेड** (ऊपर) के वाद में **तरुण प्रसाद चटर्जी बनाम दीनानाथ शर्मा** के वाद में **(2000) 8 एस. सी. सी. 649** में सूचित फैसले के कुछ पैराग्राफ उद्धृत किए हैं। **तरुण प्रसाद चटर्जी** बनाम दीनानाथ शर्मा के वाद का प्रासंगिक भाग पैराग्राफ संख्या 11 तथा 12 को यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।

> "11. ... ' शामिल या बहिष्कृत दिन।–एक समय की अवधि जब किसी दिए गए दिन या घटना से दूसरे दिन या घटना तक विधि द्वारा निर्धारित या अनुबंध द्वारा निर्धारित किया जाता है, और सवाल यह उठता है कि क्या गणना को पहले उल्लिखित या अंतिम उल्लिखित दिन के समावेशी या विशेष रूप से किया जाना है, संदर्भ और उन उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए जिनके लिए गणना की जानी है।जहां संदेह की गुंजाइश है, वहां अधिनियम या साधन का इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि वह प्रभावी हो और न कि संसद या दलों के इरादे को विफल करने के लिए, जैसा भी मामला

हो।"ऐसे दिन से" या "ऐसे दिन तक" जैसी अभिव्यक्तियाँ अस्पष्ट हैं, क्योंकि वे यह स्पष्ट नहीं करती हैं कि क्या नामित दिन को शामिल करने या बहिष्कृत करने का इरादा हो सकता है।एक सामान्य नियम के रूप में, हालांकि, इस तरह से एक अवधि को परिभाषित करने का प्रभाव पहले दिन को बाहर करना और अंतिम दिन को शामिल करना है।

“12. धारा 9 में कहा गया है कि सामान्य खंड अधिनियम, 1897 के प्रारंभ के बाद बनाए गए किसी भी केंद्रीय अधिनियम या विनियमन में, दिनों की एक श्रृंखला में या किसी अन्य अवधि में पहले को बाहर करने के उद्देश्य से, 'से' शब्द का उपयोग करना और दिनों की एक श्रृंखला में या किसी भी अवधि में अंतिम को शामिल करने के उद्देश्य से, 'से' शब्द का उपयोग करना पर्याप्त होगा।सिद्धांत यह है कि जब परिनियम या नियम द्वारा किसी अवधि का परिसीमन किया जाता है, जिसमें शुरुआत और अंत दोनों होते हैं और 'से' शब्द का उपयोग शुरुआत का संकेत देते हुए किया जाता है, तो उद्घाटन के दिन को बाहर रखा जाता है और यदि अंतिम दिन को शामिल किया जाना है तो 'से' शब्द का उपयोग किया जाता है।अवधि के पहले दिन को बाहर करने के लिए, ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या सीमा की अवधि दिनों की एक श्रृंखला या किसी निश्चित अवधि द्वारा सीमित है।इसका उद्देश्य उन कठिनाइयों या असुविधाओं को दूर करना है जो कुछ पक्षों को हो सकती हैं।उदाहरण के लिए, यदि किसी बीमा पॉलिसी को 1 जनवरी से एक दिन के लिए अच्छा होना है, तो यह उसके निष्पादन के बाद कुछ घंटों के लिए ही वैध हो सकता है और पार्टी या लाभार्थी में मान्य हो सकता है। बीमा पॉलिसी को दावा करने के लिए उचित समय नहीं मिलेगा, जब तक कि 1 जनवरी को गणना की अवधि से बाहर नहीं रखा जाता है,में मान्य हो सकता है।”

20. अपने अंतिम विश्लेषण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **इकोन एंट्री लिमिटेड** के मामले में पैराग्राफ '41' और '42' में निम्नानुसार टिप्पणी कीः

> 41. हम, इस स्तर पर, ध्यान दें कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने . हिमाचल प्र्रदेश राज्य(7) पर भरोसा किया, जहां तीन महीने की सीमा अवधि की गणना के प्रश्न पर विचार करते हुए और 30 दिनों के भीतर जिसके भीतर निर्णय को चुनौती दायर की जानी है, जैसा कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (3) और उसके परंतुक में प्रदान किया गया है, इस न्यायालय ने कहा कि सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 12 (1) और सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 9 को ध्यान में रखते हुए, जिस दिन से ऐसी अवधि की गणना की जानी है, उस दिन को सीमा की गणना के लिए बाहर रखा जाना है। प्रत्यर्थियों के वकील ने बताया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 43 सीमा अधिनियम, 1963 को मध्यस्थता अधिनियम पर लागू करती है, जबकि इसे ए परक्राम्य लिखत अधिनियम पर लागू नहीं माना जाता है और इसलिए यह निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं होगा।हमने ध्यान दिया है कि इस मामले में निर्भरता केवल सीमा अधिनियम की धारा 12 (1) पर नहीं रखी गई है। विश्वसनीयता को सामान्य खंड अधिनियम की धारा 9 पर भी रखा गया है। हालाँकि, चूंकि तत्काल मामले में हम सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 9 के आधार पर और अंग्रेजी निर्णयों की एक लंबी पंक्ति के आधार पर एक निष्कर्ष पर पहुँच गए हैं कि जहाँ एक निश्चित समय दिया गया है, एक निश्चित तिथि से, जिसके भीतर एक कार्य किया जाना है, उस तारीख के दिन को बाहर रखा जाना है, इस पर चर्चा करना आवश्यक नहीं है कि हिमाचल प्र्रदेश राज्य(7)इस मामले में लागू होता है या नहीं क्योंकि सीमा अधिनियम की धारा 12 (1) उस पर

निर्भर है।

42. इस मामले में शामिल कानून के प्रश्न पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करने के बाद, प्रासंगिक निर्णयों के आलोक में, हमारी राय है कि साकेत (2)विधि के सही प्रस्ताव को निर्धारित करता है।हमारा मानना है कि एक महीने की अवधि की गणना करने के उद्देश्य से, जो परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 142 (बी) के तहत निर्धारित है, उस अवधि की गणना उस तारीख को छोड़कर की जानी चाहिए जिस पर कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था।हमारा मानना है कि एस. आई. एल. इम्पोर्ट, यू. एस. ए.(3) सही विधि निर्धारित नहीं करता है।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस न्यायालय का कोई भी निर्णय जो इस न्यायालय द्वारा साकेत (2) में लिए गए दृष्टिकोण के विपरीत दृष्टिकोण रखता है, जिसकी हम पुष्टि करते हैं, इस संदर्भ में शामिल प्रश्न पर सही कानून निर्धारित नहीं करता है।संदर्भ का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है।

7. एच. पी. वी. राज्यहिमाचल टेक्नो इंजीनियर्स (2010) 12 एस. सी. सी. 210:(2010) 4 एस. सी. सी. (सी. वी.) 605 2.साकेत इंडिया लिमिटेड बनाम.इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड, (1999) 3 एस. सी. सी. 1:1999 एससीसी (सीआरआई) 329

3. एस. आई. एल. आयात, यू. एस. ए. बनाम निर्यात सहायक रेशम निर्यातक, (1999) 4 एस. सी. सी. 567:

21. वाद विधियो पर उपरोक्त चर्चाओं से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 9 के आधार पर, जिस तारीख को याचिकाकर्ता द्वारा अपीलीय आदेश प्राप्त किया गया था, वह सीमा की निर्धारित अवधि यानी तीन महीने की गणना में बहिष्कृत होने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन क्या यह कहा जा सकता है कि धारा 107 (1) ने सीमा की अवधि निर्धारित की है जो एक महीने को तीस दिनों के बराबर मानते हुए

नब्बे दिन होगी?

22. **बीबी सलमा खातून** (ऊपर) के वाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय सीमा के आधार पर अपील को खारिज करने वाले अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को चुनौती देने पर विचार कर रहा था। बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा क्षेत्र का निर्धारण और अधिशेष भूमि अधिग्रहण) अधिनियम, 1961 (जिसे इसके बाद '1961 का अधिनियम' कहा गया है) की धारा 16 (3) इस प्रकार हैः

> "16. (3)((i) जब इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद निकटवर्ती भूमि के सह-हिस्सेदार या रैयत के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भूमि का कोई हस्तांतरण किया जाता है, तो हस्तांतरणकर्ता का कोई सह-हिस्सेदार या हस्तांतरित भूमि से सटे भूमि रखने वाला कोई रैयत, हस्तांतरण के दस्तावेजों के पंजीकरण की तारीख से तीन महीने के भीतर, उक्त विलेख में निहित नियमों और शर्तों पर भूमि के हस्तांतरण के लिए निर्धारित तरीके से समाहर्ता के समक्ष आवेदन करने का हकदार होगाः
>
> (जोर दिया गया)
>
> बशर्ते कि ऐसा कोई भी आवेदन समाहर्ता द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि खरीद राशि को उसके दस प्रतिशत के बराबर राशि के साथ उक्त अवधि के भीतर निर्धारित तरीके से जमा नहीं किया जाता है।
>
> (ii) ऐसी जमा राशि जमा किए जाने पर सह-हिस्सेदार या रैयत भूमि के कब्जे में रखे जाने का हकदार होगा, भले ही खंड (i) के तहत आवेदन निर्णय के लिए लंबित हो।
>
> बशर्ते कि जहां आवेदन खारिज किया जाता है, वहां सह-भागीदार या रैयत , जैसा भी मामला हो, को भूमि से

> बेदखल कर दिया जाएगा और उसका कब्जा हस्तांतरणकर्ता (हस्तांतरणकर्ता) को वापस कर दिया जाएगा और हस्तांतरणकर्ता को 2024 की धारा के खंड (i) के तहत जमा की गई खरीद राशि के दस प्रतिशत के बराबर राशि भुगतान करर्ने का अधिकार होगा।
>
> (iii) यदि आवेदन की अनुमति दी जाती है, तो समाहर्ता एक आदेश द्वारा हस्तांतरणकर्ता को आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर हस्तांतरण के दस्तावेज को निष्पादित और पंजीकृत करके आवेदक के पक्ष में भूमि देने का निर्देश देगा और यदि वह निर्देश की उपेक्षा करता है या उसका पालन करने से इनकार करता है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 21 नियम 34 में निर्धारित प्रक्रिया का, जहां तक हो सके, पालन किया जाएगा।"

23. समाहर्ता के समक्ष राहत के लिए आवेदन करने के लिए प्रदान की गई सीमा की अवधि हस्तांतरण के दस्तावेज के पंजीकरण की तारीख से तीन महीने के रूप में प्रदान की गई है।एक सवाल उठा कि "महीना" शब्द का क्या अर्थ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार और उड़ीसा सामान्य खंड अधिनियम, 1917 और इंग्लैंड के हाल्सबरी के विधियो के प्रासंगिक प्रावधानों पर चर्चा की।इस मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचार बीबी सलमा खातून (उपरोक्त) के मामले में फैसले के पैराग्राफ '8' में पाए जा सकते हैं, जिसे हम यहां पुनः प्रस्तुत करते हैंः

> "8. यहाँ हम तीन महीने की निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन करने की आवश्यकता के अनुपालन से संबंधित हैं।सवाल यह उठता है कि "महीना" शब्द का क्या अर्थ है।बिहार और उड़ीसा सामान्य खंड अधिनियम, 1917 की धारा 4 की उप-धारा (34) "महीना" शब्द को ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार गिने जाने वाले महीने के रूप में परिभाषित करती है।इसका अर्थ है ग्रेगोरियन कैलेंडर-

जनवरी, फरवरी आदि। श्री झा ने 1917 के उक्त अधिनियम की धारा 11 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है ताकि यह इंगित किया जा सके कि जब "से" शब्द का उपयोग दिनों की श्रृंखला में या किसी अन्य अवधि में किया जाता है तो उसे हटा दिया जाना चाहिए और जब "से" शब्द का उपयोग दिनों की श्रृंखला में या किसी अन्य अवधि में किया जाता है, लेकिन इस मामले में "का" शब्द का उपयोग किया जाता है ताकि धारा लागू न हो।धारा 11 के अवलोकन से पता चलता है कि यह अधिनियम के प्रावधान की व्याख्या करने के बजाय प्रावधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सहायता है। जो भी हो, चूंकि अधिनियम सीमा अधिनियम की धारा 4 से 14 को स्पष्ट रूप से बाहर नहीं करता है, वे अधिनियम की धारा 16 (3) के तहत आवेदन पर लागू होते हैं। इसलिए, वह तिथि जिससे की सीमा निर्धारित की गई थी।

तीन महीने की सीमा की अवधि की गणना में शुरुआत में बाहर रखा जाना चाहिए। हैल्सबरीज लॉज ऑफ इंग्लैंड, चतुर्थ संस्करण, पैरा 211 में महीने की गणना की विधि इस प्रकार दी गई हैः

“211. मनमाने तरीके से चलने वाला कैलेंडर महीना तिथि.–जब निर्धारित अवधि किसी भी मनमाने तारीख से चलने वाला कैलेंडर महीना है, तो अवधि उस तारीख के अनुरूप बाद के महीने के उस दिन समाप्त हो जाती है जिस दिन अवधि शुरू होती है, सिवाय इसके कि, यदि अवधि एक कैलेंडर महीने के अंत में शुरू होती है जिसमें अगले महीने की तुलना में अधिक दिन होते हैं, तो अवधि उस बाद के महीने के अंत में समाप्त हो जाती है। यदि एक कैलेंडर महीने की अवधि में फरवरी का अंतिम दिन शामिल है, तो 29 या 28 दिन होने चाहिए, जैसा कि वर्ष एक अधिवर्ष है या नहीं है।” इस प्रकार संगणित, अपीलार्थी द्वारा 30-4-1988 पर दायर आवेदन सीमा के भीतर है-पंजीकृत बिक्री विलेख दिनांक

> 30-1-1988 की तारीख से तीन महीने की अवधि।मामले के इस दृष्टिकोण में, हम चुनौती के तहत आदेश को बनाए रखने में असमर्थ हैं।हम विवादित आदेश को दरकिनार करते हैं, दूसरी अपील को बहाल करते हैं और कानून के अनुसार निपटारे के लिए मामले को उच्च न्यायालय को भेजते हैं।"

24. हिमाचल टेक्नो इंजीनियर्स (उपरोक्त)**एक और वाद में**, वही प्रश्न मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत धारा 34 (3) और इसके प्रावधान के संबंध में विचार के लिए पड़ा। **हिमाचल टेक्नो इंजीनियर्स** (उपरोक्त) के निर्णय के पैराग्राफ '14', '15' और '16' को -तैयार संदर्भ के लिए यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः

> "14. उच्च न्यायालय ने माना है कि अधिनियम की धारा 34 (3) में उल्लिखित "तीन महीने" 90 दिनों की अवधि को संदर्भित करता है।यह गलत है।एक "महीना" तीस दिनों की अवधि को संदर्भित नहीं करता है, लेकिन एक कैलेंडर महीने की वास्तविक अवधि को संदर्भित करता है।यदि महीना अप्रैल, जून, सितंबर या नवंबर है, तो महीने की अवधि तीस दिन होगी।यदि महीना जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर या दिसंबर है, तो महीने की अवधि इकतीस दिन होगी।यदि महीना फरवरी है, तो यह अवधि उनतीस दिन या अट्ठाईस दिन होगी, जो इस बात पर निर्भर करती है कि यह एक अधिवर्ष है या नहीं।
>
> एडःखंड में चौथे संस्करण के पहले अंक में देखें। 45, पैरा 1111
>
> 15. अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (3) और उसके लिए महत्वपूर्ण रूप से परंतुक, उन इकाइयों में उल्लिखित समय की अवधि को व्यक्त नहीं करते हैं। उप-धारा (3) में सीमा की अवधि निर्धारित करते समय "तीन महीने" शब्दों का उपयोग किया गया है और

परंतुक में क्षम्य विलंब की बाहरी सीमा का उल्लेख करते हुए "तीस दिन" शब्दों का उपयोग किया गया है। विधायिका के पास समान इकाइयों में समय की अवधि का वर्णन करने का विकल्प था, यानी अवधि को क्रमशः "तीन महीने" और "एक महीने" के रूप में वर्णित करना या अवधि को क्रमशः "नब्बे दिन" और "तीस दिन" के रूप में वर्णित करना।ऐसा नहीं किया।इसलिए, विधायिका का इरादा यह नहीं था कि उप-धारा (3) में उपयोग की जाने वाली तीन महीने की अवधि को 90 दिनों के बराबर माना जाए, और न ही इसका इरादा था कि तीस दिनों की अवधि को एक महीने के रूप में लिया जाए।

16. सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3 (35) एक "महीने" को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार गिना गया महीना।"

25. हाल के एक फैसले में, **पश्चिम बंगाल राज्य** बनाम **राजपथ ठेकेदार और इंजीनियर लिमिटेड,** (ऊपर) **के मामले में** माननीय उच्चतम न्यायालय ने मध्यस्थता और समेकन अधिनियम, 1996 की धारा 34 की उप-धारा 3 और सीमा अधिनियम की धारा 4 पर विचार किया। उक्त मामले में यह पाया गया कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा 30 जून, 2022 को दिया गया निर्णय उसी दिन अपीलार्थी को दिया गया था।धारा 34 की उप-धारा 3 के तहत याचिका दायर करने की सीमा की अवधि उस तारीख से तीन महीने है जिस दिन आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थता पुरस्कार प्राप्त हुआ था या यदि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 33 के तहत अनुरोध किया गया था, उस तारीख से जिस दिन मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा उस अनुरोध का निपटारा किया गया था।सीमा अवधि का प्रारंभिक बिंदु 1 जुलाई, 2022 था, इसलिए यह माना गया कि तीन महीने की अवधि का अंतिम दिन यानी 30 सितंबर, 2022 सीमा अवधि होगी। उक्त मामले में, स्वीकार किया

जाता है कि धारा 34 की उप-धारा 3 के तहत आवेदन 30 सितंबर, 2022 तक दायर नहीं किया गया था।उच्च न्यायालय में पूजा अवकाश 1 अक्टूबर, 2022 से शुरू हुआ और 30 अक्टूबर, 2022 (दोनों दिन सहित) तक जारी रहा।मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत याचिका 31 अक्टूबर, 2022 को दायर की गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पाया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 43 के आधार पर, सीमा अधिनियम मध्यस्थों पर लागू होगा जैसा कि यह न्यायालय की कार्यवाही पर लागू होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सीमा अधिनियम की धारा 4 पर विचार किया जो इस प्रकार हैः

> **"4. निर्धारित अवधि की समाप्ति जब न्यायालय बंद हो।**
>
> जहाँ किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित अवधि उस दिन समाप्त हो जाती है जब न्यायालय बंद हो जाता है, उस दिन वाद, अपील या आवेदन स्थापित किया जा सकता है, उसे प्राथमिकता दी जा सकती है या उस दिन किया जा सकता है जब न्यायालय फिर से खुलेगा।
>
> स्पष्टीकरण।–एक अदालत को इस धारा के अर्थ के भीतर किसी भी दिन बंद माना जाएगा यदि वह अपने सामान्य कार्य घंटों के किसी भी हिस्से के दौरान उस दिन बंद रहती है।"

26. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राजपथ कॉन्ट्रैक्टर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड** (उपरोक्त) के सन्दर्भ में **असम शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम सुभाष प्रोजेक्ट्स और एम. के. टी. जी. (2012) 2 एस. सी. सी. 624** में अधिसुचित का उल्लेख किया, और उक्त निर्णय के पैराग्राफ '13' का हवाला दिया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि

1963 के अधिनियम की धारा 4 में महत्वपूर्ण शब्द "निर्धारित अवधि" हैं। इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर विचार करना शुरू किया और जवाब दिया कि **राजपथ ठेकेदारों और इंजीनियरों** के मामले में सीमित (ऊपर) चूंकि वर्तमान मामले में सीमा अधिनियम की धारा '4' के लागू होने के संबंध का कोई मुद्दा शामिल नहीं है। हमें उस मुद्दे में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह कहना पर्याप्त है कि इस मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि तीन महीने की अवधि 30 सितंबर को समाप्त हो गई।यदि दिनों में विरोध किया जाता है, तो यह '92' दिन होगा, इसलिए, यह इस विषय पर एक और बाध्यकारी मिसाल है।

27. इस स्तर पर, हमें **मैसर्स वैष्णवी एंटरप्राइजेज** (उपरोक्त) के मामले में विद्वत समन्वय पीठ के फैसले पर ध्यान देना चाहिए। राज्य ने इस फैसले पर भरोसा किया है।उक्त निर्णय को नंगे पढ़ने पर, हम पाते हैं कि विद्वत समन्वय पीठ ने यह विचार रखा है कि अपील में दिनांक 14.05.2023 के आदेश के खिलाफ, अपील 12.08.2023 पर या उससे पहले दायर की जानी थी और यदि आवश्यक हो तो उसके बाद एक महीने के भीतर अर्थात 11.09.2023 पर या उससे पहले विलंब माफी आवेदन के साथ दायर की जानी थी।विद्वत समन्वय पीठ ने पाया कि अपील केवल 20.03.2024 पर दायर की गई थी, सीमा अवधि समाप्त होने के बाद।इस प्रकार, मैसर्स वैष्णवी एंटरप्राइजेज (उपरोक्त) में, विद्वत समन्वय पीठ ने 90 दिनों की अवधि के रूप में तीन महीने की सीमा की अवधि ली।

28. सबसे पहले, हम पाते हैं कि उक्त मामले में, अपील सीमा की निर्धारित अवधि की समाप्ति की तारीख से एक महीने के

बाद दायर की गई थी। हालाँकि, वर्तमान मामले में, वास्तव में हम पाते हैं कि तीन महीने की सीमा की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद एक महीने के भीतर अपील की गई थी।जहाँ तक विद्वत समन्वय पीठ की टिप्पणियों का संबंध है कि 12.08.2023 पर या उससे पहले अपील दायर की जानी चाहिये थी का अवलोकन विधि और उच्च न्यायालय के बाध्यकारी उदाहरणों की अज्ञानता में है।

29. कालिका कौर (ऊपर) के वाद में, माननीय उच्चतम न्यायालय को इस बात पर विचार करने में खुशी हुई है कि किन परिस्थितियों में किसी निर्णय को अनवधानता (पर- इनकुएरीउम) के अनुसार दिया गया माना जा सकता है। **कालिका कौर** (ऊपर) के वाद में निर्णय के पैराग्राफ '5' और '6' को तैयार संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः

> **5.** इस मोड़ पर हम इस बात की जांच कर सकते हैं कि किन परिस्थितियों में किसी निर्णय को पर- अनवधानता के अनुसार दिया गया माना जा सकता है। हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड (चौथा संस्करण) खण्ड. 26:निर्णय और आदेशः प्राधिकारियों के रूप में न्यायिक निर्णय (पीपी 297-98, पैरा 578) में हम पाते हैं कि यह लगभग अनवधानता के अनुसार इस प्रकार देखा गया हैः "अनवधानता के अनुसार निर्णय तब दिया जाता है जब न्यायालय ने अपने स्वयं के या समन्वय क्षेत्राधिकार के न्यायालय के पिछले निर्णय की अज्ञानता में कार्य किया हो, जो उसके समक्ष मामले को कवर करता है, जिस मामले में उसे यह तय करना चाहिए कि किस मामले का पालन करना है (2) या जब उसने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के निर्णय की अज्ञानता में कार्य किया है, तो उस मामले में उसे उस निर्णय का पालन करना चाहिए; या जब

निर्णय किसी क़ानून या नियम की शर्तों की अज्ञानता में दिया जाता है जो वैधानिक बल (3) है। किसी निर्णय को अनवधानता के अनुसार नहीं माना जाना चाहिए, हालांकि, केवल (4) पक्षों की कमी के कारण, या क्योंकि न्यायालय को सर्वोत्तम तर्क का लाभ नहीं मिला था, और एक सामान्य नियम के रूप में, केवल ऐसे मामले जिनमें निर्णय दिए जाने चाहिए, वे हैं जो किसी असंगत क़ानून या बाध्यकारी प्राधिकरण की अज्ञानता में दिए गए हैं। भले ही अपील न्यायालय के किसी निर्णय ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पिछले निर्णय की गलत व्याख्या की हो, अपील न्यायालय को अपने पिछले निर्णय का पालन करना चाहिए और गलती को सुधारने के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स को छोड़ना चाहिए।"(7)

2. [यंग बनाम ब्रिस्टल एयरप्लेन कंपनी लिमिटेड, 1944 KB 718 729:(1944) 2 300 पर सभी ई. आर. 293। हडर्सफील्ड पुलिस प्राधिकरण बनाम वाटसन, 1947 के. बी. 842:(1947) 2 सभी ईआर 193।]

3. [यंग बनाम ब्रिस्टल एयरप्लेन कंपनी लिमिटेड, 1944 KB 718 729:(1944) 2 300 पर सभी ई. आर. 293. लैंकेस्टर मोटर कंपनी (लंदन) लिमिटेड बनाम भी देखें। ब्रेमिथ लिमिटेड, (1941) 1 के. बी. 675:(1941) 2 सभी ई. आर. 11.उस अदालत द्वारा अवहेलना किए गए डिवीजनल कोर्ट के फैसले के लिए, निकोलस बनाम पेनी, (1950) 2 के. बी. 466 देखें।(1950) 2 सभी ईआर 89।].4. [मोरेले लिमिटेड बनाम.वाकलिंग (1955) 2 क्यू. बी. 379:(1955) 1 सभी ईआर 708 (सीए)]

5.[ब्रायर्स बनाम कैनेडियन पैसिफिक स्टीमशिप्स लिमिटेड, (1957) 1 क्यूबी 134:(1956) 3 सभी ई. आर. 560 (सी. ए.) प्रति सिंगलटन, एल. जे., कैनेडियन पैसिफिक स्टीमशिप्स लिमिटेड बनाम में पुष्टि की गई। ब्रायर्स 1958 एसी 485:(1957) 3 सभी ई. आर. 572।]

6.[ए. और जे. मकलो लिमिटेड बनामआई. आर. सी.,

1954 सीएच 615:(1954) 2 सभी ई. आर. 508 (सी. ए.), मोरेल लिमिटेड बनाम.वाकलिंग (1955) 2 क्यू. बी. 379:(1955) 1 सभी ई. आर. 708 (सी. ए.), बोनसर बनाम संगीतकार संघ, 1954 चै. 479 भी देखें। (1954) 1 सभी ई. आर. 822 (सी. ए.), जहां प्रति अनवधानता विवाद खारिज कर दिया गया था और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपील पर, हालांकि सदन ने अपील न्यायालय को बाध्य करने वाले मामले को खारिज कर दिया था, सदन ने सहमति व्यक्त की कि वह न्यायालय इसके द्वारा बाध्य था; बोनसर बनाम संगीतकार संघ, 1956 ए. सी. 104 देखें।(1955) 3 सभी ईआर 518 (एचएल)।]

7. [विलियम्स बनाम ग्लासब्रुक ब्रदर्स लिमिटेड, (1947) 2 सभी ई. आर. 884 (सी. ए.)] हडर्सफील्ड पुलिस प्राधिकरण मामले 2 में लॉर्ड गोडार्ड, मुख्य न्यायाधीश द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि जहां कोई वाद या विधि न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था और न्यायालय ने मामले या क़ानून के अस्तित्व के बारे में अज्ञानता या भूल में निर्णय दिया था, तो यह अनवधानता के अनुसार दिया गया निर्णय होगा।

6. इस न्यायालय के एक निर्णय में आंध्राप्रदेश सरकार बनाम बी. सत्यनारायण राव(8) मे यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया हैः(एस. सी. सी. पी. 264-65, पैरा 8)

> "अनवधानता का नियम तब लागू किया जा सकता है जब कोई न्यायालय उसी न्यायालय या उसी मुद्दे पर दिए गए उच्च न्यायालय के बाध्यकारी उदाहरण पर विचार करने से चूक जाती है या जहां कोई अदालत उस मुद्दे पर निर्णय लेते समय किसी भी विधि पर विचार करने से चूक जाती है।...इसलिए हम पाते हैं कि वर्तमान मामले में पर अनवधानता का नियम लागू नहीं किया जा सकता है।इसके अलावा, किसी मामले को केवल किसी पक्ष के

> कहने पर बड़ी पीठ को नहीं भेजा जा सकता है। दो न्यायाधीशों के निर्णय का दो अन्य समन्वय न्यायाधीशों की पीठ पर बाध्यकारी है, जब तक कि यह प्रदर्शित नहीं किया जाता है कि विधि या निर्णय में किसी भी बाद के परिवर्तन के कारण उक्त निर्णय सही कानून की व्याख्या नहीं कर रहा हो ।"

30. ऊपर उद्धृत माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से, हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान मामले में, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि 27.03.2024 पर समाप्त हो गई है। अपीलार्थी एक महीने की और अवधि के भीतर अपील कर सकता था, अर्थात अपीलीय प्राधिकारी को यह संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त कारण दर्शाते हुए कि अपीलार्थी को एक महीने की आगे की अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।इस मामले में, 26.04.2024 पर अपील दाखिल की गई थी, इसलिए, अपीलीय प्राधिकरण को विलंब को माफ करने के लिए अपीलार्थी द्वारा दिखाए गए कारण पर विचार करने की आवश्यकता थी।

2. [यंग बनाम ब्रिस्टल एयरप्लेन कंपनी लिमिटेड, 1944 KB 718 729:(1944) 2 300 पर सभी ई. आर. 293।हडर्सफील्ड पुलिस प्राधिकरण बनाम वाटसन, 1947 के. बी. 842:(1947) 2 सभी ईआर 193।]

8. [(2000) 4 एससीसी 262:

31. हमारा मानना है कि अपीलीय प्राधिकरण ने सी. जी. एस. टी./बी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 107 के तहत विधायी योजना का अधिमुल्यन करने में पूरी तरह से गलती की है। विधायिकाओं ने स्पष्ट रूप से प्रावधान किया है कि अपील दायर करने की सीमा की अवधि तीन महीने की होगी और इसे एक महीने की और अवधि के भीतर प्रस्तुत

किया जा सकता है, बशर्ते कि अपीलीय प्राधिकरण को निर्धारित अवधि के भीतर अपील को प्राथमिकता न देने के लिए पर्याप्त कारण दिखाया जाए।

32. अनुलग्नक 'पी/4' में निहित 18.05.2024 दिनांकित आक्षेपित आदेश को इसके द्वारा दरकिनार किया जाता है। रिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

33. अपीलीय प्राधिकारी अपील को अपनी मूल फाइल में बहाल करेगा और याचिकाकर्ता द्वारा तीन महीने जो सीमा की निर्धारित अवधि है, के भीतर अपील को दाखिल नहीं करने के लिए दिखाए गए कारणों पर विचार करेगा । हम मानते हैं और घोषणा करते हैं कि 26.04.2024 पर प्रस्तुत की गई अपील एक महीने की आगे की अवधि के भीतर है जैसा कि सी.जी.एस.टी/बी.जी.एस.टी अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा 4 के तहत परिकल्पित है।

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति)

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

ऋषि/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।